



## राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम

### प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम, राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी) ।

### मेन्स के लयः

संपत्तः मुद्राकरण और संबधति चुनौतयः, संपत्तः मुद्राकरण योजना और लाभ ।

## चर्चा में क्यः?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूरण स्वामतः वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम **National Land Monetization Corporation- NLMC**) की स्थापना को मजूरी दी है ।

- वतः मंत्रः ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इस उद्देश्य के लयः एक वशः प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) स्थापति करने की योजना की घोषणा की थी ।
- अगस्त, 2021 में भारत सरकार ने [राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन](#) (National Monetisation Pipeline- NMP) का शुभारंभ कयः ।

## प्रमुख बडु

### राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण नगिम(NLMC):

- NLMC के बारे में:**
  - NLMC एक एजेंसी के रूप में अधशः भूमि संपत्तः मुद्राकरण का कार्य करेगा और इस संबध में केंद्र को सहायता व तकनीकी सलाह प्रदान करेगा ।
  - NLMC की घोषणा 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ की गई है ।
  - NLMC के नदःक मंडल में कंपनी के पेशेवर संचालन और प्रबंधन को सक्रम करने के लयः केंद्र सरकार के वरषुठ अधिकारी और प्रतषुठति वशःज्ज शामिल होंगे ।
    - NLMC के अध्यक्ष, गैर-सरकारी नदःकों की नयुक्तःयोग्यता-आधारति चयन प्रक्रयः के माध्यम से की जाएगी ।
  - नई कंपनी को वतः मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में स्थापति कयः जाएगा ।
  - NLMC नजी क्षेत्र के पेशेवरों को उसी तरह नयुक्त करेगी जैसे कः समान वशःट सरकारी कंपनयः के मामले में होता है जैसे [राष्ट्रीय नदः और बुनयःदी ढाँचा कःष \(NIIIF\)](#) और [इन्वेस्ट इंडयः](#) ।
- लाभ:**
  - यह नजी क्षेत्र के नदः, नई आर्थिक गतवधःयः, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढावा देने तथा आर्थिक एवं सामाजिक बुनयःदी ढाँचे हेतु वतःतीय संसाधन उत्पन्न करने के लयः कम उपयोग की गई संपत्तःयः के उत्पादक उपयोग को सक्रम करेगा ।
  - NLMC से यह भी उम्मीद की जाती है कः वःह बंद होने वाले CPSE की अधशः भूमि और भवन संपत्तः तथा रणनीतिक वनःवःष के तहत सरकारी स्वामतः वाले सीपीएसई की अधशः गैर-प्रमुख भूमि संपत्तः का स्वामतः, प्रबंधन एवं मुद्राकरण करेगा ।
    - इससे सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रयः में तेजी आएगी जससे सरकारी स्वामतः वाले सीपीएसई की रणनीतिक वनःवःष प्रक्रयः आसान होगी ।
- चुनौतयः:**
  - NLMC को जनि प्रमुख चुनौतयः का सामना करना** पड़ सकता है उनमें वशः रूप से भूमि संपत्तःयः में पहचान योग्य राजस्व की कमी, वःवःद समाधान तंत्र, वःभःनःन मुकदमे और स्पष्ट शीर्षक की कमी तथा दूरस्थ भूमि पारसल में नदःकों के बीच कम रुचः शामिल है ।

## NLMC का कार्य:

- NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि भवन संपत्तिका मुद्रीकरण करेगा।
  - CPSEs वे कंपनियाँ हैं जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSE की सीधी हस्तिसेदारी 51% या उससे अधिक है।
  - वर्तमान में CPSE के पास भूमि और भवनों की प्रकृति में काफी अधिशेष, अपरयुक्त और कम उपयोग की गई गैर-प्रमुख संपत्तियाँ हैं।
- NLMC अन्य सरकारी संस्थाओं (CPSEs सहित) को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख संपत्तियों की पहचान करने और अधिकतम मूल्य प्राप्त हेतु पेशेवर और कुशल तरीके से उनका मुद्रीकरण करने में सलाह और समर्थन देगा।
- NLMC भूमि मुद्रीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार के रूप में कार्य करेगा, परसंपत्तिका मुद्रीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा।

## संपत्तिका मुद्रीकरण क्या है?

- **परिचय:**
  - यह अपरयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्तिका आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके सरकार और उसकी संस्थाओं के लिये राजस्व के नए स्रोत बनाने की प्रक्रिया है।
- **आवश्यकता:**
  - भारत को और अधिक बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के पास इसके निर्माण के लिये संसाधन नहीं हैं। इस संबंध में दो संभावित प्रतिक्रियाएँ हैं।
    - नया बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिये नज्दी क्षेत्र को एक संवदात्मक ढाँचे के तहत इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
    - चूँकि निर्माण चरण के तहत अधिक जोखिम होता है, इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र के तहत संपत्तिका निर्माण किया जा सकता है और फरि इसे नज्दी क्षेत्र को बेचा जा सकता है या फरि नज्दी क्षेत्र को इसका प्रबंधन सौंपा जा सकता है।
  - भारत सहित किसी भी देश के लिये नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण में दो बाधाएँ हैं -
    - अनुमानित और सस्ती पूंजी तक पहुँच और
    - नष्पादन क्षमता, जहाँ सरकारी एवं नज्दी एजेंसियाँ एक साथ कई प्रमुख परियोजनाएँ ले सकती हैं।
- **संबंधित चुनौतियाँ:**
  - विभिन्न संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव।
  - सरकारी कंपनियों में नज्दीकरण की धीमी रफ्तार।
  - इसके अलावा ट्रेनों में हाल ही में शुरू की गई PPP पहल में उत्साहजनक बोलियों से यह संकेत मिलता है कि नज्दी नविशकों की रुचि को आकर्षित करना इतना आसान नहीं है।
  - **संपत्तिका-विशिष्ट चुनौतियाँ:**
    - गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का नमिन स्तर।
    - वदियुत क्षेत्र की परसंपत्तियों में वनियमिति टैरफि।
    - फोर लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये नविशकों में कम दिलचस्पी।
    - उदाहरण के लिये कोंकण रेलवे में राज्य सरकारों सहित कई हतिधारक हैं, जिनकी कंपनी में हस्तिसेदारी है।

## आगे की राह

- **बहु-हतिधारक दृष्टिकोण:** बुनियादी ढाँचे की वसितार योजना की सफलता अन्य हतिधारकों संबंधी उनकी उचित भूमिका नभाने पर नरिभर करेगी।
  - इनमें राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम व नज्दी क्षेत्र शामिल हैं।
  - इस संदर्भ में पंद्रहवें वतित आयोग ने केंद्र और राज्यों के वतितिय उत्तरदायित्व कानून की फरि से जाँच करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह की स्थापना की सफिराशि की है।
- पारदर्शिता बनाए रखना परसंपत्तिका मूल्य की पर्याप्त प्राप्ति की कुंजी है।
- हाल के अनुभव से पता चलता है कि सार्वजनिक-नज्दी भागीदारी (पीपीपी) में अब पारदर्शी नीलामी, जोखिमों और अदायगी की स्पष्ट समझ व सभी इच्छुक पार्टियों के लिये एक खुला क्षेत्र शामिल है।
  - इस प्रकार ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में पीपीपी की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

## स्रोत: पी.आई.बी.